# नकदी की तंगी से जूझ रहे मिस्र ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए पारगमन शुल्क में 10% तक की बढ़ोतरी की

नकदी की कमी से जूझ रहे मिस्र ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांजिट शुल्क में 10% तक की बढ़ोतरी की है।

स्वेज नहर प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि वृद्धि "वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि के अनुरूप" थी और नहर के "पारगमन सेवा के विकास और वृद्धि" का हवाला दिया।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, रासायनिक टैंकरों और अन्य तरल थोक टैंकरों के लिए पारगमन शुल्क में 10% की वृद्धि हुई। वाहनों, प्राकृतिक गैस और सामान्य कार्गो, साथ ही बहुउद्देश्यीय जहाजों को ले जाने वाले जहाजों में 7% की वृद्धि देखी जाएगी, जबकि तेल और कच्चे टैंकरों और सूखे थोक जहाजों पर 5% की वृद्धि की जाएगी। वैश्विक शिपिंग में बदलाव के अनुसार बढ़ोतरी को बाद में संशोधित या बंद किया जा सकता है।

नहर के अधिकारी जलमार्ग के दक्षिणी हिस्से को चौड़ा और गहरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जहां मार्च 2021 में एक हॉकिंग जहाज ने नहर को बंद कर दिया था।

छह दिन की रुकावट ने वैश्विक शिपमेंट को बाधित कर दिया। कुछ जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबा वैकल्पिक मार्ग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए अतिरिक्त ईंधन और अन्य लागतों की आवश्यकता थी। रुकावट खत्म होने के लिए सैकड़ों अन्य जहाज जगह-जगह इंतजार कर रहे थे।

विश्व के 7% तेल सहित वैश्विक व्यापार का लगभग 10% स्वेज नहर के माध्यम से बहता है, जो भूमध्यसागरीय और लाल समुद्र को जोड़ता है। मिस्र के लिए, नहर - जो पहली बार 1869 में खुली - राष्ट्रीय गौरव और विदेशी मुद्रा दोनों का स्रोत है।

## स्वेज़ नहर:

स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए मिस्र में स्वेज के इस्तमुस के पार उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाला एक कृत्रिम समुद्री स्तर का जलमार्ग है। यह नहर अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। यह यूरोप और भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के आसपास की भूमि के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। यह दुनिया की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है, जो विश्व व्यापार का 12% से अधिक मात्रा में ले जाती है।

# भेदभाव शून्य दिवस 01 मार्च को मनाया गया

समाज में भेदभाव एक भयावह बुराई के रूप में प्रचलित रहा है जो मनुष्यों की हमारी समझ में उस अंतर्निहित गड़बड़ी को उजागर करता है।

मनुष्य के रूप में, हमने खुद को लिंग पहचान, जाति, वर्ग, यौन अभिविन्यास, लिंग, व्यवसाय, आय, विकलांगता आदि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है।

शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी बाधा के बावजूद गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सकें।

शून्य भेदभाव दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोगों को समावेश, करुणा, शांति और सबसे बढ़कर, परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के बारे में सूचित किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है।

शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद कर रहा है।

**दिन का विषय:** शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय: "नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं", यूएनएड्स भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहा है।

## दिन का इतिहास:

शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था, और दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर UNAIDS द्वारा अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू करने के बाद बीजिंग में UNAIDS के कार्यकारी निदेशक द्वारा शुरू किया गया था।

## UNAIDS

एचआईवी और एड्स पर संयुक्त संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) एचआईवी/एड्स महामारी पर त्वरित, व्यापक और समन्वित वैश्विक कार्रवाई का मुख्य समर्थक है।

**मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

**कार्यकारी निदेशक:** विनी ब्यानिमा

**संस्थापक:** पीटर पियोटा

**स्थापित:** 26 जुलाई 1994

## ऑपरेशन गंगा: बुडापेस्ट से छठी उड़ान 240 भारतीयों के साथ दिल्ली में उतरी

हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से ऑपरेशन गंगा के तहत 240 भारतीय नागरिकों को लेकर छठी निकासी उड़ान 28 फरवरी 2022 को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया।

**'ऑपरेशन गंगा':** यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है।

इसके तहत, भारत पहले ही देश से अपने 1,000 से अधिक नागरिकों को सफलतापूर्वक वापस ला चुका है।

इसने हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ सीमा पार बिंदुओं के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता के लिए 24×7 नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए हैं।

## विज्ञान सर्वत्रे पूज्यते विज्ञान सप्ताह महोत्सव का लेहो में समापन

विज्ञान सर्वत्रे पूज्यते विज्ञान सप्ताह महोत्सव 28 फरवरी 2022 को लेह में संपन्न हुआ।

आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लेह देश के उन 75 केंद्रों में से एक है, जहां विज्ञान सप्ताह मनाया जाता है।

लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर के अनुसार, लद्दाख को यूनेस्को के सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजी को प्राप्त करने में विज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है।

एसडीजी में खाद्य सुरक्षा, जन्म दर और शिक्षा में डिजिटल साक्षरता और पारिस्थितिक रूप से स्मार्ट भविष्य शामिल हैं।

## फरवरी में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ के पार

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, फरवरी 2022 के महीने में एक लाख 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया।

इस साल फरवरी महीने का राजस्व संग्रह पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 18 प्रतिशत अधिक और फरवरी 2020 में जीएसटी राजस्व से 26 प्रतिशत अधिक है।

जीएसटी संग्रह अब तक पांचवीं बार एक लाख 30 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है।

**गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी):** भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर (या उपभोग कर) है।

कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब में विभाजित किया गया है: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।

## नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम (Artemis Program) की चंद्रमा पर पहली क्रू लैंडिंग, वर्ष 2026 में होने की संभावना

NASA के अनुसार, मानव के सतह पर उतरने संबंधी प्रणाली (Human Landing System) और नासा के अगली पीढ़ी के स्पेससूट के विकास और परीक्षण हेतु अभी और अधिक्त समय चाहिए।

आर्टेमिस (ARTEMIS) का पूरा नाम "ऐक्सेलरैशन, रीकनेक्शन, टर्ब्युलन्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ़ मून'स इंटरएक्शन विद द सन" (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of Moon's Interaction with the Sun) अर्थात चंद्रमा का सूर्य के साथ अंतःक्रिया का गतिवर्धन, पुन:संयोजन, विक्षोभ तथा विद्युत्-गतिकी है। यह नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अगला मिशन है।

इसका उद्देश्य, चंद्रमा की चट्टानी सतह, जहाँ इसकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है- पर सूर्य का विकिरण के टकराने के प्रभाव को मापना है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में, 'आर्टेमिस' अपोलो की जुड़वां बहन और चंद्रमा की देवी थी।

आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत, नासा द्वारा वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर पहली बार किसी महिला को तथा अगले पुरुष को उतारा जाएगा।

स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) नामक नासा के शक्तिशाली नए रॉकेट से 'ओरियन अंतरिक्ष यान' में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग सवा लाख मील की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा।

अंतरिक्ष यात्री 'ओरियन यान' को गेटवे (Gateway ) पर डॉक करेंगे और चंद्रमा की सतह पर अभियान हेतु मानव लैंडिंग सिस्टम में पहुंचेंगे।

अभियान की समाप्ति पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने हेतु फिर से ओरियन पर सवार होने लिए 'कक्षीय चौकी' (orbital outpost) पर लौट आएंगे। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एवं आर्टेमिस 3:

आर्टेमिस 1 (Artemis 1) का लक्ष्य, एक बार उड़ान भरने वाले ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ, अभी तक एक बार भी उडान नहीं भरने वाले 'स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट' के संयोजन का उपयोग करके चंद्रमा के चारों ओर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजना है।

आर्टेमिस 2 (Artemis 2): वर्ष 2024 में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले आर्टेमिस 2 मिशन को लांच करने के साथ, नासा द्वारा आर्टेमिस कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना है।

इसके बाद वर्ष 2020 के दशक में भेजे जाने वाले अन्य चालक दल सहित मिशनों से पहले वर्ष 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन भेजा जाएगा।

# रूस-यूक्रेन संकट का सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक स्तर पर कमी पर प्रभाव

रूस और यूक्रेन, वैश्विक स्तर पर 'अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला' (Semiconductor Supply Chain) के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये दोनों देश इस उद्योग के लिए 'पैलेडियम' जैसी दुर्लभ धातुएं और 'नियॉन' जैसी गैसें उपलब्ध कराते हैं, जिनका लगभग सभी आधुनिक उपकरणों और उपकरणों में मौजूद सिलिकॉन वेफर्स के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। मौजूदा रूस-यूक्रेन संकट के बीच, तनाव एवं युद्ध की स्थिति 'सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक स्तर पर कमी' को और खराब कर सकती है।

जिस तरह, वैश्विक अर्धचालक उद्योग (Semiconductor Industry) के लिए रूस दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति करता है, उसी तरह यूक्रेन, चिप-उत्पादन उद्योग के लिए आवश्यक गैसों की आपूर्ति करता है। इस प्रकार, अर्धचालकों की आपूर्ति श्रृंखला में तनाव बढ़ाने की संभावना है। सेमीकंडक्टर चिप्स, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ऑटो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर्स (Semiconductors) – जिन्हें एकीकृत सर्किट (आईसी), या माइक्रोचिप्स के रूप में भी जाना जाता है – प्रायः सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे यौगिक से निर्मित होते हैं।

‘सेमीकंडक्टर चिप्स’, सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ‘सूचना और संचार प्रौद्योगिकी’ उपकरणों के ‘दिल और दिमाग’ के रूप में कार्य करने वाले बुनियादी ‘बिल्डिंग ब्लॉक्स’ होते हैं।

ये चिप्स अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीनों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। कोविड -19 महामारी की वजह से, दिन-प्रतिदिन की आर्थिक और आवश्यक गतिविधियों के बड़े हिस्से को ऑनलाइन रूप से किए जाने या इन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाए जाने के दबाव ने, लोगों के जीवन में चिप-संचालित कंप्यूटर और स्मार्टफोन की ‘केंद्रीयता’ को उजागर कर दिया है।

दुनिया भर में फ़ैली महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सहित देशों में ‘महत्वपूर्ण चिप बनाने वाली सुविधाओं’ को भी बंद कर दिया गया।

‘सेमीकंडक्टर चिप्स’ की कमी का व्यापक अनुवर्ती असर पड़ता है। पहले ‘चिप्स’ का अधिक मात्रा में भंडारण किए जाने से इसकी मांग में वृद्धि होती है, जो बाद में आपूर्ति में कमी का कारण बन जाती है।

## हाल ही में आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया गया

हाल ही में, ‘अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन समिति’ (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट (Sixth Assessment

Report) का दूसरा भाग जारी किया गया। रिपोर्ट के इस दूसरे भाग में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और कमजोरियों और अनुकूलन विकल्पों के बारे में आकलन किया गया है। रिपोर्ट का पहला भाग, पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था, जोकि जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार पर केंद्रित था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल' (IPCC) की छठी आकलन रिपोर्ट (Sixth Assessment Report – AR6), जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक जानकारी का आकलन करने के उद्देश्य से तैयार की जाने वाली रिपोर्टों की एक श्रृंखला में छठी रिपोर्ट है। अब तक, क्रमशः 1990, 1995, 2001, 2007 और 2015 में पांच आकलन रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं। नवीनतम रिपोर्ट में, पहली बार, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय और क्षेत्रीय प्रभावों का आकलन किया गया है।

इसमें दुनिया भर के मेगा-शहरों के समक्ष खड़े जोखिमों और उनकी कमजोरियों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ का उच्च जोखिम मजूद है, जबकि अहमदाबाद में ग्रीष्म लहरों का गंभीर खतरा है। पहली बार, आईपीसीसी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों का अवलोकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से- विशेष रूप से एशिया के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में- मलेरिया और डेंगू जैसे वेक्टर जनित और जल जनित रोगों में वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में भारत को एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसके कई क्षेत्र और महत्वपूर्ण शहर बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि और ग्रीष्म लहरों जैसी जलवायु आपदाओं के बहुत अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। मुंबई, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ के उच्च जोखिम का सामना कर रहा है।

आईपीसीसी की स्थापना, वर्ष 1988 में 'विश्व मौसम विज्ञान संगठन' (WMO) और 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)' के द्वारा की गयी थी।

**मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड

*****